

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग - 1

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2011

विषय: सचिवालय अनुदेश, 1982 में उल्लिखित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 818/xxvii(1)/2009 दिनांक: 8 दिसम्बर, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सचिवालय अनुदेश 1982 के नियम 25 तथा 26(1) में यह व्यवस्था है कि ऐसे समस्त प्रस्ताव जिनमें राज्य के वित्त पर प्रभाव पड़ता हो, पर आदेश जारी किये जाने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा तथा वित्त विभाग के विचार प्रशासकीय विभाग के स्थायी अभिलेख में अंकित किये जायेंगे एवं वे मामले से सम्बन्धित पत्रावली के भाग होंगे।

कतिपय मामलों में यह अनुभव किया गया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा ऐसे प्रकरण, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हैं, उनका निस्तारण वित्त विभाग को पत्रावली न भेजकर बैठकों के माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया सचिवालय अनुदेश के उक्त प्राविधान के अनुरूप नहीं है।

बैठकों के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य केवल अन्वेषणात्मक प्रकृति (exploratory nature) का होता है, जिसमें सामूहिक रूप से विचार मंथन (brain storming) के आधार पर एक विभागीय मत स्थिर किया जाता है। बैठक में भाग लेने वाले वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त मत को, वित्त विभाग का आधिकारिक अभिमत नहीं माना जाना चाहिए तथा इसका तदनुसार उपयोग/व्याख्या ऐसे निर्णयों को लेने में नहीं किया जा सकता है, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हो। वित्त विभाग का आधिकारिक मत वही होगा जो प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर उनके प्रस्ताव के सन्दर्भ में अंकित किया गया हो। इस प्रकार बैठकों में वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर प्रकरण का निस्तारण उचित नहीं है।

स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के किसी प्रकरण में बैठक में लिया गया निर्णय निर्धारित प्रक्रियानुसार पत्रावली पर वित्त विभाग का मन्तव्य प्राप्त करने का विकल्प नहीं हो सकता है। अतः जिन मामलों में प्रशासनिक विभाग की पत्रावली पर वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त करके निर्णय लिया जाना हो उनके सम्बन्ध में वित्त विभाग को पत्रावली सन्दर्भित करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये।

सचिवालय अनुदेश की व्यस्थानुसार उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,


(सुभाष कुमार)

मुख्य सचिव।

संख्या- 66 /xxvii-1/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।